RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 250
दि. 10.01.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

कड़ाके की ठंड में 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 29 शहरों में शीतलहर, आईएमडी की नई चेतावनी

(जीएनएस)।

देश के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कहीं घना कोहरा सड़कों को निगल रहा है तो कहीं सर्द हवा हड्डियों तक चुभ रही है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी क्टऊ ने 10 जनवरी 2026 के लिए ऐसा अपडेट जारी किया है जिसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर और पूर्वी भारत के 29 शहर शीतलहर की गिरफ्त में हैं तो दक्षिण के चार राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है।

पहाड़ों से लेकर मैदान और समुद्र तक मौसम का मिजाज एक साथ बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्टऊके मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में अगले पांच से सात दिनों तक सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है।

मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी अगले दो से तीन दिनों तक यही हाल रहने वाला है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति बनने वाली है यानी दिन में भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी।

कहां कहां चलेगी शीतलहर?

10 और 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी है। 10 जनवरी को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार भी इसी ठंडे झटके की चपेट में रहेंगे।

राजस्थान में 11 से 14 जनवरी तक शीतलहर का असर बना रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने वाला है और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की भी आशंका जताई गई है।

चार राज्यों में बारिश बढ़ाएगी टेंशन

दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे अवदाब ने दक्षिण भारत का मौसम उलट कर रख दिया है। क्टऊ ने अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के लिए 10 जनवरी को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 जनवरी को भी कुछ इलाकों में तेज बरसात हो सकती है।

इस बारिश से इन राज्यों में तापमान तीन से चार डिग्री तक गिर सकता है जिससे ठंडक और बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी और आसपास के समुद्री इलाकों में समुद्र बहुत उग्र रहने वाला है इसलिए मछुआरों को तट से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है।

तमिलनाडु तट पर समुद्र का रौद्र रूप

तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के पास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। खाड़ी एरिया और गल्फ ऑफ मन्नार में समुद्र की हालत बहुत खराब रहने वाली है। ऐसे में किसी भी तरह की समुद्री गतिविधि खतरनाक साबित हो सकती है।

29 शहर में कोल्ड वेब का अलर्ट

पूर्वी भारत में बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, लखीसराय, पटना और सिवान में शीतलहर का असर तेज रहेगा। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग में बाहर निकलना मुश्किल होगा।

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, आगरा, टुंडला, अलीगढ़ और गौतमबुद्ध नगर में सुबह के समय तेज सर्द हवा के साथ शीतलहर चलेगी। हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत और कुरुक्षेत्र तथा पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर और पटियाला भी इसी ठंड की चपेट में हैं।

दिल्ली एनसीआर में ठंड का डबल अटैक

दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में शीतलहर बनी रहने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी ने इस सर्दी की सबसे ठंडी सुबह देखी और कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। ठंडी हवाओं के साथ नमी बढ़ने से कोहरा और गलन दोनों लोगों को परेशान कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में मिलेगी हल्की राहत

यूपी के लोगों को अगले दो दिनों में कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि धूप निकलने से कोहरा और ठंड थोड़ी कम होगी। हालांकि कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह राहत अस्थायी मानी जा रही है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्की धुंध बनी रह सकती है।

बिहार में शीत दिवस का खतरा

बिहार में 10 और 11 जनवरी को शीत दिवस की स्थिति बनने की चेतावनी है। दिन के तापमान में सामान्य से ज्यादा गिरावट हो सकती है। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा में घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम रहने वाली है।

कश्मीर में जमी डल झील, कड़ाके की ठंड जारी

कश्मीर घाटी इस समय चिल्ला ए कलां की चपेट में है जो 29 जनवरी 2026 तक चलेगा। श्रीनगर में तापमान हिमांक से कई डिग्री नीचे चला गया है और डल झील के कुछ हिस्से जम चुके हैं। क्टऊके अनुसार 21 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा लेकिन बादल छाए रहेंगे। 10 जनवरी तक रात का तापमान और गिर सकता है उसके बाद एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी संभव है।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ठंड का जोर

राजस्थान में अगले दो से तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की और गिरावट हो सकती है और यह सामान्य से दो से चार डिग्री नीचे रहेगा। छत्तीसगढ़ में हिमालय से आ रही सर्द हवाओं ने तापमान गिरा दिया है। 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है और पिछले 28 दिनों में ठंड से तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत कई जिलों में हल्की बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

हमारी नीति किसी के दवाब में नहीं बदलेगी', ट्रंप की धमकी पर भारत का करारा जवाब

(जीएनएस)।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने हालिया प्रेस वार्ता में वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीति पर भारत का कड़ा रुख स्पष्ट किया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिका द्वारा रूस से ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर प्रस्तावित 500% टैरिफ के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके साथ ही, मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ते सैन्य तनाव पर भी अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता

अमेरिका के प्रस्तावित 500% टैरिफ बिल पर भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति किसी बाहरी दबाव में नहीं बदलेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की जरूरतों के लिए 'सस्ती ऊर्जा' जुटाना प्राथमिकता है। भारत ग्लोबल मार्केट के बदलते स्वरूप के अनुसार अलग-अलग स्रोतों से तेल और यूरेनियम खरीदना जारी रखेगा। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक संप्रभु मुद्दा है, जिसे बाजार की गतिशीलता और घरेलू जरूरतों के आधार पर ही तय किया जाएगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर दिए गए बयानों का खंडन किया है। टएअ प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि दोनों देश पिछले साल फरवरी से एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए निरंतर बातचीत कर रहे हैं। भारत ने लुटनिक की टिप्पणियों को 'गलत' बताते हुए कहा कि हम कई बार समझौते के बेहद करीब रहे हैं।

: घाटकोपर मेट्रो को 7 साल के इंतजार के बाद मिलेगी ये सुविधा, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

मुंबई मेट्रो के सबसे व्यस्त घाटकोपर स्टेशन को आखिरकार 7 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिलने वाली है। लंबे समय तक

यात्रियों की मांग और मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। घाटकोपर स्टेशन के मुंबई मेट्रो एंड पर प्रस्तावित चौड़ा एलिवेटेड डेक बनने का रास्ता साफ हो गया है। यह डेक स्टेशन के उस हिस्से पर बनाया जा रहा है, जहां मेट्रो लाइन-1 (ब्लू लाइन) से उतरने वाले हजारों यात्री सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेनों से जुड़ते हैं।

ईील्लॅ' ए ीू३ङ्घल्ल 2026: इस बार ळटउ छोड़ बीजेपी का झंडा थाम सकती हैं फेमस एक्ट्रेस नुसरत जहां, मिल रहे नए संकेत!

इ८ ¯र३ं ट४ॅ

ळी वस्र्शिीि: ऋ८िं, खंल्ल४१८ 9, 2026, 18:08 [क्रळ]

ईील्लॅ' ए ीू३ङ्घल्ल 2026 ठ४२१ं३ खंॅल्ल: अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (ळटउ) की पूर्व सांसद नुसरत जहां फिर चर्चा में हैं। उनके पार्टनर और अभिनेता यश दासगुप्ता को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कयासों का दौर शुरू हो गया है। यश दासगुप्ता बीजेपी के टिकट पर चुनाव

80 लाख किसानों का इंतजार खत्म! खाते में आएंगे 2000 रुपये

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के करीब 83 लाख किसान इन दिनों एक ही सवाल पूछ रहे हैं-मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त आखिर कब आएगी? दो महीने बीतने को हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 2000 रुपये की अगली किस्त को लेकर अब तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत 19 नवंबर को किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है।

11 जनवरी को मिलेगा पैसा?

अब किसानों की नजरें 11 जनवरी पर टिकी हैं। इस दिन भोपाल में एक बड़े किसान सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृषि वर्ष 2026 की औपचारिक घोषणा करेंगे। कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा।

हालांकि सम्मेलन के जारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का कहीं जिक्र नहीं है। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि 11 जनवरी को भी किसानों को 2000 रुपये की सीधी सौगात नहीं मिलेगी, हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सम्मेलन के दौरान 14वीं किस्त की संभावित तारीख का ऐलान किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान खेती को लाभ का धंधा बनाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर रहेगा। लेकिन राज्य की सबसे अहम किसान सहायता योजना की अगली किस्त में हो रही देरी सरकार के लिए सवाल खड़े कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि 14वीं किस्त फरवरी 2026 तक टल सकती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में नवगठित शामलाजी तहसील में विकास उत्सव मनाया गया

प्रसिद्ध यात्राधाम शामलाजी में शामलाजी महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री की प्रेरक उपस्थिति

शामलाजी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की

अरवल्ली जिले को 168 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी

गांधीनगर, 09 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शामलाजी में मनाए जा रहे शामलाजी महोत्सव का समापन करते हुए अरवल्ली जिले को 168 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी।

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शामलाजी को नई तहसील घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला कार्यक्रम- शामलाजी महोत्सव पूरे अरवल्ली जिले के लिए विकास उत्सव बन गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा अरवल्ली जिले के लिए पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत किए गए 1232 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों और वंचितों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए विकास कार्यों में कभी धन की कमी नहीं पड़ने दी है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 'विकास भी, विरासत भी' मंत्र से

धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की दिव्यता एवं भव्यता को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास करने का दृष्टिकोण साकार किया है।

उन्होंने साफ कहा कि जनजातीय क्षेत्रों को आवास, अभ्यास (शिक्षा), आजीविका और आरोग्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर उप जिला अस्पताल बनाए जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन जनजातीय क्षेत्रों में 12 साइंस कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी और 11 मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से आदिवासी परिवारों की संतानों के लिए भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने की दिशा खुली है।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदिवासियों की परंपरागत कला, कौशल, पेशों और उत्पादनों को वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के माध्यम से प्रोत्साहन देने का भी आह्वान किया।

मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने अभूतपूर्व विकास किया है।

विशेषकर, अरवल्ली जिले के आदिवासी क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

राज्य मंत्री श्री पी.सी. बरंडा ने कहा कि शामलाजी महोत्सव आदिवासी समुदाय की एकता, संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक है और इस वर्ष हजारों लोगों की भागदारी और कलाकारों के लोकसंगीत, नृत्य एवं भक्तिमय वातावरण से समुदाय की विरासत और अधिक मजबूत बनी है। उन्होंने कहा कि आज मिले विकास कार्यों और लोकार्पण से अरवल्ली के विकास को और गति मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क एवं भवन विभाग (राज्य) की 107.02 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, शिक्षा विभाग की 24.49 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, खेल विभाग की 19.9 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, सड़क एवं भवन विभाग (पंचायत) की 12.5 कोरड़ रुपए की परियोजनाओं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 3.46 करोड़ रुपए की परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

'मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव', एऊरेड के बाद ममता का चौंकाने वाला दावा, कोलकाता से दिल्ली तक हड़कंप

(जीएनएस)।

कोलकाता की सड़कों पर गुस्सा, हाथों में पोस्टर और मंच से सीधे केंद्र सरकार को खुली चुनौती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के बाद जो कहा, उसने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया। ममता ने ऐलान कर दिया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो वह कोयला घोटाले की पूरी परतें खोल देंगी।

8 जनवरी को ईडी ने ळटउ के आईटी सेल प्रमुख और क-ढअउ से जुड़े प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। इसके बाद ळटउ ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध का बिगुल फूंक दिया। खुद ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर 9 जनवरी को उतरीं, मार्च निकाला और ईडी के खिलाफ दो एफआईआर भी दर्ज कराईं।

ममता सिर्फ विरोध तक नहीं रुकीं। वह रेड के दौरान जांच स्थल पर भी पहुंचीं और वहां से फाइलें और पेन ड्राइव लेकर बाहर आईं। उनका कहना था कि ईडी उनके पार्टी के संवेदनशील चुनावी डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश कर रही थी।

भीड़ को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि उनके पास अमित शाह से जुड़े पेन ड्राइव हैं। उनका दावा था कि कोयला घोटाले का पैसा दिल्ली तक पहुंचता है और इसमें सीधे गृह मंत्री का नाम जुड़ा है। ममता ने कहा कि वह अपने पद की गरिमा की वजह से अब तक चुप थीं, लेकिन अगर उन्हें उकसाया गया तो वह सबकुछ जनता के सामने रख देंगी।

उनका आरोप था कि इस घोटाले के पैसे का इस्तेमाल सुवेंदु अधिकारी ने किया और वही रकम अमित शाह तक पहुंचाई गई। ममता ने कहा कि पूरे देश को तब झटका लगेगा, जब ये सबूत सामने आएंगे।

ममता बनर्जी ने कहा,

"दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। कोयला घोटाले का पैसा सुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं ऐसे तो प्रतिक्रिया नहीं देतीं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं।"

ममता ने कहा,

"मेरे पास पेन ड्राइव हैं। मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूं, उसकी इज्जत करते हुए चुप रही हूं। मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो। मैं सब कुछ बता दूंगी। पूरा देश चौंक जाएगा।"

बीजेपी नेताओं पर सीधे हमले

ममता ने सिर्फ अमित शाह का ही नहीं, बल्कि बंगाल के कई बीजेपी नेताओं का भी नाम लिया। उन्होंने सांसद जगन्नाथ सरकार को "डकैत" कहा और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को "गद्दार" और अमित शाह का "नया दत्तक पुत्र" बताया। ममता का आरोप था कि कोयला घोटाले का पैसा इन्हीं रास्तों से घूमकर ऊपर तक गया।

उन्होंने बीएसएफ और सीआईएसएफ पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर ये एजेंसियां ईमानदारी से काम करतीं तो अवैध कोयला तस्करी रुक सकती थी।

चुनाव आयोग और रक्फ़ पर भी निशाना

ममता ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में बैठा एक अधिकारी पहले अमित शाह के सहयोगी विभाग में काम कर चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी व्यक्ति से निजी आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह हरियाणा और बिहार में सत्ता हासिल की गई, वही मॉडल अब बंगाल में लागू किया जा रहा है।

उन्होंने रक्फ़ के नाम पर बंगाली बोलने वालों को परेशान करने का आरोप लगाया। ममता का कहना था कि बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा और बंगालियों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है, जबकि असम में रोहिंग्या होने के बावजूद वहां ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।

सम्पादकीय

मादुरो के सत्ता से हटाये जाने से पहले सीआईए का गोपनीय आंकलन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए सैन्य अभियान को अधिवृत करने से ठीक पहले अमेरिका की गुप्तचर सेवा सीआईए ने एक गोपनीय आंकलन पूरा किया जिसमें यह जांच की गई कि अगर मादुरो को अचानक सत्ता से हटा दिया जाता है तो वेनेजुएला की आंतरिक स्थिति वैसी होगी? न्यूयार्व टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप द्वारा प्रात्यक्ष कार्रवाई के जोखिमों और परिणामों का आवंलन करने के दौरान वरिष्ठ प्राशासनिक अधिकारियों ने गुप्त विश्लेषण का अनुरोध किया था। रिपोर्ट में अमेरिका के नेतृत्व में तख्तापलट की संभावना पर कम और मादुरो के लिए व्यावहारिक निकास परिदृष्टियों पर अधिक ध्यान वेंद्रित किया गया था, जिसमें बातचीत के माध्यम से समझौते, निरन्तर अमेरिकी दबाव और अंतिम उपाय के रूप में बल प्रायोग शामिल थे।

खुफिया आंकलन से अवगत लोगों ने बताया कि सीआईए ने मादुरो के पद छोड़ने के लिए एक ही संभावित परिणाम की कल्पना करने के बजाए कई विकल्पों पर विचार किया। इनमें बातचीत के जरिए सत्ता हस्तांतरण शामिल था, जिसमें मादुरो स्वेच्छा से पद छोड़ देते, प्रातिबंधों और संपत्ति जब्ती के माध्यम से दबाव बढ़ाना और अन्य विकल्पों के विफल होने पर जबरन निष्कासन की संभावना शामिल थी। इस विश्लेषण का उद्देश्य ट्रंप द्वारा द्वारा वेनेजुएला के एक अत्याधिक सुरक्षित सैन्य ठिकाने के खिलाफ उच्च जोखिम वाले अभियान की मंजूरी देने पर विचार करते समय उच्चस्तरीय निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना था। रिपोर्ट से परिचित अधिकारियों ने कहा कि इसमें राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय को प्राभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीआईए की नजर में सबसे संभावित उत्तराधिकारी कौन था? इस आकलन के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षो में से एक उत्तराधिकारी पर इनका दृष्टिकोण था, उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगज। रोड्रिगज को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जो मादुरो को हटाए जाने की स्थिति में तुरन्त सत्ता संभालने के लिए सबसे उपयुक्त थीं। हालांकि वुछ सांसदों और वेनेजुएला के नागरिकों ने विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को संभावित वैकल्पिक नेता के रूप में देखा है, लेकिन खुफिया समीक्षाओं ने इस बात पर संदेह जताया है कि क्या उनके पास मादुरो के बाद की स्थिति में जल्दी से सत्ता संभालने के लिए आवश्यक संगठनात्मक ढांचा या राजनीतिक प्रायास है? खुफिया जानकारी से परिचित अधिकारियों के अनुसार सीआईए को संदेह था कि क्या विपक्ष जनसमर्थन को राज्य संस्थाओं, सेना और सुरक्षा सेवाओं पर प्राभावी नियंत्रण में बदल पाएगा? चिता वैचारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक थी, स्पष्ट और व्यवहार्य उत्तराधिकारी के बिना मादुरो को हटाने से अस्थिरता कम होने के बजाए और बढ़ सकती थी। सीआईए का यह आंकलन सही साबित होता दिख रहा है। वेनेजुएला में न तो सत्ता परिवर्तन हुआ और न ही मौजूदा सरकार और देशवासियों में अमेरिका के प्राति समर्थन बढ़ता दिख रहा है।

निकोलस मादुरो को तो हटा दिया पर फिलहाल उनके उत्तराधिकारी डेल्सी रोड्रिगज वैसी ही बातें कर रही हैं जैसे मादुरो करते थे। आगे चलकर बदल जाए तो और बात है। अभी तो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति, डेल्सी रोड्रिगज ने कहा है कि देश पर वेनेजुएला की सरकार शासन कर रही है, न कि कोई विदेशी शक्ति। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि उन्हें वेनेजुएला तक पूरी पहुंच चाहिए। रोड्रिगज ने कहा यहां कोई युद्ध नहीं है क्योंकि हम युद्ध में नहीं हैं।

हम एक शांतिप्रिय लोग हैं। एक शक्तिशाली देश हैं, जिस पर हमला किया गया और आव्रमण किया गया। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारी 3 से 5 करोड़ बैरल प्रातिबंधित तेल अमेरिका को हस्तांतरित करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह चिंतन शिविर नए भारत के निर्माण में माइनिंग सेक्टर का रोडमैप तैयार करने का सक्षम मंच बनेगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सेक्टर में होलिस्टिक एप्रोच के साथ रिफॉर्म्स लाए हैं
- गुजरात लिग्नाइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट जैसे मुख्य खनिजों के लिए एक अहम क्षेत्र
- गुजरात अपनी खनिज संपदाओं के द्वारा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत से 'विकसित भारत@2047' का संकल्प साकार करने में योगदान देने को प्रतिबद्ध

भारत का खनन क्षेत्र 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी

खनिज संपदा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल

बिहार के उप मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के खान मंत्री हुए सहभागी

गांधीनगर, 09 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा गुरुवार को महात्मा मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर में कहा कि यह चिंतन शिविर नए भारत के निर्माण का रोडमैप तैयार करने का एक सक्षम मंच बनेगा।

केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में प्रथम तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें देश के विभिन्न राज्यों के खान मंत्री और पदाधिकारियों सहित हितधारक भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों सर्वश्री जी. किशन रेड्डी, सी.आर. पाटिल, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय खान राज्य मंत्री सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस तीन दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खान-खनिज देश के उद्योगों एवं अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह चिंतन शिविर सामूहिक चिंतन-मंथन के माध्यम से इस आधार स्तंभ को और मजबूत बनाकर देश के विकास को एक नई गति देने का प्लेटफार्म प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सेक्टर में होलिस्टिक एप्रोच के साथ रिफॉर्म्स (सुधार) लाए हैं। खनन क्षेत्र भी ऐसे रिफॉर्म्स का साक्षी रहा है। स्पष्ट नीतियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारदर्शी शासन के परिणामस्वरूप ये रिफॉर्म्स संभव हो पाए हैं।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करने की जो परंपरा स्थापित की है, और ग्रीन माइनिंग, साइंटिफिक रेक्लेमेशन और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी से खनन क्षेत्र का विकास किया है।

मुख्यमंत्री ने गुजरात को लिग्नाइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट जैसे मुख्य खनिजों के लिए एक अहम स्थान बताते हुए कहा कि खान-खनिज क्षेत्र को केवल उत्पादकता और नीलामी तक सीमित न रखते हुए गुजरात ने इसे पारदर्शिता, अनुशासन और नियम-कानूनों के अमल का प्रतीक भी बनाया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खान से लेकर अंतिम गंतव्य स्थल तक के खनिज परिवहन की रीयल टाइम निगरानी के लिए जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात अपनी खनिज संपदाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' से 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को साकार करने को प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री

जी. किशन रेड्डी ने खनन क्षेत्र को भारत के आर्थिक विकास और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मजबूत आधार स्तंभ करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुजरात आज पूरे देश के लिए विकास का केंद्र बन गया है। गुजरात के मॉडल का अनुसरण करके आज देश के अनेक राज्यों के बीच विकास और निवेश के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरूआत हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने पिछले 11 वर्षों में खनन क्षेत्र में आए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2014 की तुलना में मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी खनिज अन्वेषण में 190 फीसदी की वृद्धि हुई है। आयरन, लाइमस्टोन, लेड और जिंक जैसे खनिजों के उत्पादन में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। पारदर्शी नीलामी प्रणाली और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमडब्ल्यू) के माध्यम से राज्यों के खनन राजस्व में बड़ा उछाल आया है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और टंगस्टन जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल खनिजों के निष्कर्षण (पृथ्वी से खनिज निकालने की प्रक्रिया) तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिफाइनिंग, रीसाइक्लिंग और रीप्रोसेसिंग की पूरी 'वैल्यू चेन' पर ध्यान दे रहा है। वर्ष 2030 तक ई-वेस्ट से क्रिटिकल मिनरल्स को रिकवर करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्षों के लिए रणनीतिक योजना तैयार करना है। इसमें खनिज ब्लॉकों की नीलामी से लेकर ऑपरेशन तक के समय को न्यूनतम करना, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण का उपयोग बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके भारत को ग्लोबल प्रोसेसिंग हब बनाना जैसे विषयों पर अधिकतम फोकस करना शामिल है।

इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के पुनर्उपयोग के लिए 'अर्बन माइनिंग' और 'वेस्ट टू वेल्थ' के विचार को गति देने का आह्वान किया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में खनिज क्षेत्र और जल प्रबंधन का परस्पर समन्वय बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जब 'विकसित भारत' बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, ऐसे में खनिज संपदा को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहना गलत नहीं होगा। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति में इस मंत्रालय की भूमिका निर्णायक है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि खनिज उत्खनन के दौरान पर्यावरण और जल संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने 'माइनिंग विद माइंडफुलनेस' का मंत्र देते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन के साथ खनन कार्य करने से ही दीर्घकालिक लाभ होगा। खनन प्रक्रिया में पानी का रीसाइकल और रीयूज अनिवार्य है। उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से उपयोग करने की बात कही जिससे भूमिगत जलस्तर को नुकसान न पहुंचे।

श्री पाटिल ने कहा कि भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर हम आयात पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, जो देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाएगी और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करेगी। शिविर के दौरान उन्होंने खान विभाग द्वारा अपनाई गई पारदर्शिता और कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाली डिजिटल और नवीन पद्धतियों की प्रशंसा की।

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने चिंतन शिविर को भारत के खनन क्षेत्र के भविष्य के लिए एक निर्णायक मार्ग बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए वर्ष 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संग्रह के लिए आवश्यक बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 'क्रिटिकल मिनरल्स' के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ऐसी खानों की नीलामी और उत्पादन प्रक्रिया को तेज बना रही है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक उपकरणों का खनन क्षेत्र में उपयोग अनिवार्य है, जिससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि प्रदूषण, लागत और समय में भी उल्लेखनीय बचत होगी।

खनिज विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए श्री दुबे ने कहा कि खनन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करना और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ किया कि इस क्षेत्र में केवल सरकार की भागीदारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के साथ कदम मिलाकर चलना होगा।

चिंतन शिविर के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय खनन सचिव श्री पीयूष गोयल ने स्वागत भाषण दिया।

कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मंत्री श्री कोल्लू रवीन्द्र, ओडिशा के मंत्री श्री विभूति भूषण जेना, तेलंगाना के मंत्री श्री विवेक वेंकट स्वामी, उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉ. अरुण कुमार, नागालैंड के मंत्री श्री चीनवेंग, गुजरात की उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा सहित केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

एप्लीकेशन के 3 दिन बाद जॉइनिंग,करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव, लालू परिवार का 7 डील वाला खेल

बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला 'नौकरी के बदले जमीन' मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और अन्य 41 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी में इस पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित 'सिंडिकेट' की तरह संचालित बताया है।

सीबीआई (उइक) की जांच में दावा किया गया है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के विभिन्न जोन में बिना किसी विज्ञापन या

पारदर्शी प्रक्रिया के लोगों को ग्रुप-डी की नौकरियां दी गईं। इसके बदले में अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से कौड़ियों के भाव बेशकीमती जमीनें लिखवाई गईं। यह मामला न केवल एक परिवार की कानूनी लड़ाई है, बल्कि भारतीय राजनीति और सत्ता के दुरुपयोग की गहरी पड़ताल भी है।

'निजी जागीर' की तरह इस्तेमाल हुआ मंत्रालय

9 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में विशेष न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रेल मंत्रालय को उस दौरान एक 'निजी जागीर' की तरह चलाया गया। कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत कुल 41 लोगों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (ढउ अू३) और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, सबूतों के अभाव में 52 अन्य लोगों को राहत भी दी गई है।

ये भी पढ़ें: छंल्ला ऋ्क्क१ खड्ड उंरी: लालू परिवार पर शिकंजा, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 41 पर आरोप तय, अब जाना होगा जेल!

कैसे शुरू हुई जांच? 3.75 लाख की जमीन और 3 नौकरियां

इस घोटाले की परतें तब खुलनी शुरू हुई जब पटना के किशुन देव राय का मामला सामने आया। 6 फरवरी 2008 को किशुन देव ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन बाजार भाव से कहीं कम, महज 3.75 लाख रुपए में राबड़ी देवी के नाम कर दी। सौदे के तुरंत बाद किशुन देव के परिवार के तीन सदस्यों को मुंबई स्थित मध्य रेलवे में नौकरी मिल गई। यहीं से जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के ठोस संकेत मिले।

4.39 करोड़ की जमीन सिर्फ 26 लाख में

उइक के अनुसार, 2004 से 2009 के बीच लालू परिवार ने भ्रष्टाचार के जरिए बिहार में एक लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन हासिल की।

कीमत का अंतर: जिस जमीन की बाजार कीमत उस समय लगभग 4.39 करोड़ रुपए थी, उसे सिर्फ 26 लाख रुपए में हथिया लिया गया।

बिना विज्ञापन भर्ती: मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे रेलवे जोन में नियुक्तियों के लिए कोई आधिकारिक विज्ञापन नहीं निकाला गया।

तीन दिन में जॉइनिंग: कुछ मामलों में तो आवेदन देने के मात्र 3 दिन के भीतर ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए।

सात जमीन सौदों में छिपा 'भ्रष्टाचार का मॉडल'

जांच एजेंसी ने कोर्ट के सामने सात ऐसे प्रमुख सौदों का जिक्र किया है, जो इस घोटाले की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हैं:

किशुन देव राय: जमीन के बदले परिवार के 3 सदस्यों को नौकरी मिली।

संजय राय: 3.75 लाख में जमीन दी, बदले में परिवार के 2 लोगों को रेलवे में काम मिला।

किरण देवी: मीसा भारती को जमीन बेची, अगले साल बेटे का चयन रेलवे में हो गया।

निजी कंपनी का खेल: हजारी राय की जमीन पहले 'एके इन्फोसिस्टम्स' जैसी कंपनी को दी गई, जिसका नियंत्रण बाद में लालू परिवार के पास आ गया।

लाल बाबू राय: बेटे को 2006 में नौकरी मिली और 2015 में जमीन राबड़ी देवी के नाम की गई।

गिफ्ट डीड: एक कर्मचारी ने नौकरी मिलने के बाद 62 लाख की जमीन लालू परिवार को 'गिफ्ट' कर दी।

हेमा यादव: रेलवे में नौकरी मिलने के कुछ समय बाद जमीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव के नाम ट्रांसफर की गई।

एऊ की कार्रवाई और 600 करोड़ की संपत्ति

इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (एऊ) ने अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित या जब्त किया है। इसमें दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित पॉश बंगला भी शामिल है। उइक का दावा है कि कई जमीनों को महज 5,700 रुपए जैसी मामूली रकम पर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम किया गया था, जबकि उस समय वे नाबालिग थे। आरोप तय होने के बाद अब 29 जनवरी 2026 से इस मामले का औपचारिक ट्रायल शुरू होगा।

कौन ये वाला सलमान खान, जो में भीड़ को उकसाने में बुरा फंसा? खुद बताई पूरी सच्चाई?

(जीएनएस)।

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में 6-7 जनवरी 2026 की रात एमसीडी की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा ने शहर को हिला दिया। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे हटाने पर भीड़ ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर हमला हुआ और कई जवान घायल हो गए। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, और CCTV फुटेज से 30 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान की है।

इस हिंसा में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (क्ल्ला'श्लील्ली१) का नाम भी जुड़ रहा है, जिनमें से एक है हाजी सलमान खान। आरोप है कि सलमान ने वीडियो और ऑडियो मैसेज के जरिए लोगों को भड़काया और मस्जिद के पास इकट्ठा होने के लिए उकसाया। लेकिन सलमान ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। आइए, इस सलमान की बैकग्राउंड, आरोपों की सच्चाई और पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। यह कहानी सोशल मीडिया की ताकत और गलत इस्तेमाल की है, जो हिंसा को भड़का सकती है...

तुर्कमान गेट इलाका दिल्ली का पुराना और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। 6 जनवरी की रात एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की। यहां बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानें थीं, जो कथित तौर पर मस्जिद की जमीन पर बनी थीं। कार्रवाई के दौरान लोकल लोग इकट्ठा हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस पर हमला हुआ, जिससे कई जवान घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

इस हिंसा को 'सुनियोजित' बताया जा रहा है। पुलिस जांच में पता चला कि सोशल मीडिया पर अफवाहें

फैलाई गईं - जैसे ' मस्जिद गिराई जा रही है' । व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम पर मैसेज फॉरवर्ड हुए, जिससे भीड़ इकट्ठी हुई। अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और 10 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार है, जिनके पोस्ट्स स्कैन हो रहे हैं। सलमान खान इन्हीं में से एक हैं।

हाजी सलमान खान (उम्र: करीब 30-35 साल) गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और खुद को 'डिजिटल क्रिएटर' बताते हैं। सलमान की पहचान मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से जुड़ी है - वे अल्पसंख्यक अधिकारों, सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक कैंपेन पर पोस्ट करते हैं। सलमान खुद को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रभार में ळटउ (तृणमूल कांग्रेस) के प्रदेश मंत्री बताते हैं, और ढटखश (प्रधानमंत्री जन विकास योजना) के प्रचार-प्रसार अभियान से जुड़े हैं। शिक्षा और बैकग्राउंड: सलमान ने मेरठ के शुभार्ती यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की रवाडी (पालखी यात्रा) में ढोल-ताशों ने जमाया भारी आकर्षण

ढोल-ताशों के 50 कलाकारों द्वारा उमंगोल्लासपूर्ण वादन के साथ यात्री भी नाच उठे, तीन ढोल टूटे

गांधीनगर, 09 जनवरी : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत शुक्रवार को भव्य रवाडी (पालखी यात्रा) के दौरान समग्र सोमनाथ नगरी भक्ति एवं उत्साह से गूंज उठी। रवाडी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्त तथा श्रद्धालु बड़ी संख्या में सहभागी हुए।

इस रवाडी के दौरान ढोल-ताशा कलाकारों ने अपनी मनमोहक तथा उमंगोल्लासपूर्ण प्रस्तुति से विशेष आकर्षण उत्पन्न किया। लगभग 50 कुशल कलाकारों ने ढोल और ताशों के ताल-लय के साथ परंपरागत संगीत की

प्रस्तुति कर वातावरण को रंगीन बना दिया। गगनभेदी नाद के साथ यात्री भी नाच उठे। वादन इतना उत्साहपूर्ण था कि लगभग तीन ढोल टूट गए। ढोल-ताशों के गूंजते नाद के साथ रवाडी आगे बढ़ रही थी, जिसके कारण मार्ग के दोनों ओर खड़े दर्शकों में भी उत्साह दिखाई दे रहा था। कलाकारों की एकीकृत प्रस्तुति ने समग्र कार्यक्रम को लोकोत्सव के स्वरूप में रूपांतरित कर दिया।

रवाडी के दौरान भक्तों द्वारा जय शिवशंकर तथा हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सनातन संस्कृति की महिमा गुंजाई गई। ढोल-ताशों के ताल के साथ भक्ति तथा आनंद का अनूठे संगम का सृजन हुआ।

इस प्रकार; सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत निकली रवाडी में ढोल-ताशा कलाकारों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम की भव्यता तथा सांस्कृतिक वैभव को और उजागर कर सभी उपस्थितों के लिए इस क्षण को यादगार बना दिया।

हनी सिंह पर टिकी स्मृति मंधाना की नजर, ओपनिंग सेरेमनी हुआ कुछ ऐसा कि वीडियो हो रहा वायरल

(जीएनएस)।

शुक्रवार की शाम को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में विमेंस प्रीमियर लीग (हढछ) चौथे सीजन का आगाज हुआ। टूनार्मेंट की शुरूआत धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ की गई। कार्यक्रम की शुरूआत मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू के एक दमदार भाषण से हुई। उन्होंने समाज में महिला शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

हनी सिंह की दमदार एंट्री (हढछ 2026, ल्ङ्घल्लीट ल्ल्ँ)

हरनाज कौर संधू के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज ने अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फिल्म 'किक' के मशहूर गाने 'यार ना मिले' पर जबरदस्त डांस मूव्स दिखाए। शाम का सबसे बड़ा आकर्षण रहे रैपर यो यो हनी सिंह। सिर से पैर तक काले पहनावे में सजे हनी सिंह ने जैसे ही अपने सुपरहिट गाने 'मिलियनेयर' के साथ मंच पर एंट्री की, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा।

हनी पर टिकी मंधाना की नजर

हनी सिंह के साथ आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना और मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी नजर आईं। हनी सिंह के गानों और उनके डांस स्टेप्स ने सीजन की शुरूआत में जोश भर दिया। इस दौरान मंधाना की नजरें हनी पर टिक गई

जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस धमाकेदार आगाज के बाद सीजन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (फ्छइ) की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (टक) के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

आरसीबी ने जीता टॉस

मंधाना ने बताया कि रात में ओस की भूमिका को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। ग्रेस हैरिस, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ और नडीन डी क्लर्क के रूप में आरसीबी ने अपने चार विदेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया। वहीं मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि स्टार खिलाड़ी हेली मैथ्यूज तबीयत खराब होने के कारण इस ओपनिंग मैच का हिस्सा नहीं बन सकीं।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) योजना अंतर्गत एक दिवसीय जनपद स्तरीय किसान मेला एवं सह प्रदर्शनी का आयोजन

एसएसडी

बक्शी का तालाब, 8 जनवरी

बक्शी का तालाब स्थित चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय एक दिवसीय किसान मेला एवं सह-प्रदर्शनी, कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन कृषि विभाग जनपद लखनऊ के द्वारा किया गया। मेला एवं प्रदर्शनी की शुरूआत बक्शी का तालाब के क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला ने फीता काटकर की तथा प्रदर्शनी का अवलोकन किया एव सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर मेला एवं प्रदर्शनी की शुरूआत की । उप कृषि निदेशक विनय कौशल ने आत्मा योजना की रूपरेखा एवं कृषि विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। तथा सभी किसानों, शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों तथा छात्र -छात्राओं का स्वागत किया। कृषि विभाग के सलाहकार सुरेश कुमार राजपूत ने मेला एवं प्रदर्शनी की रुपरेखा बतायी तथा प्राकृतिक खेती पर विस्तृत चर्चा की। कृषि विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ ए के दुबे ने समसामयिक फसलों में कीट रोग प्रबंधन तथा अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों पर चर्चा किया। अपर जिला कृषि अधिकारी हर्षित त्रिपाठी ने मृदा के गिरते स्वास्थ्य पर चर्चा की और कहा की समय पर किसानों को मिट्टी की जांच कराना चाहिए तथा दलहनी खेती पर जोर दिया। । मुख्य अतिथि योगेश शुक्ला ने प्रदेश सरकार की जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी दी तथा बताया कि किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है जिससे जनपद के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कृषि महाविद्यालय के कृषि कीट विज्ञान विभाग के सह -आचार्य डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने आलू और सरसों की खेती तथा उन पर लगने वाले रोग एवं कीटों पर पर चर्चा की। इरादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक दयाशंकर सिंह ने एफपीओ के बारे में विधिवत बताया तथा एफपीओ से ही किसानों की आय बढ़ सकती है।

दिल्ली वाले सावधान! राजधानी में 2 दिन पानी की किल्लत, कौन-कौन से इलाके होंगे प्रभावित?

(जीएनएस)।

दिल्लीवासियों को अगले दो दिनों तक पानी की भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड (ऊखइ) ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 9 जनवरी 2026 की शाम और 10 जनवरी 2026 की सुबह राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद या बेहद कम प्रेशर पर रहेगी।

जल बोर्ड के मुताबिक, यह असुविधा पाइपलाइन इंटरकनेक्शन वर्क और जलाशयों की सालाना फ्लशिंग प्रक्रिया की वजह से हो रही है। ऊखइ ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से पानी स्टोर कर लें। जानिए किन-किन इलाकों में पानी नहीं आएगा... इंद्रावल वाटर वर्क्स के अंतर्गत आने वाले जलाशयों में वार्षिक फ्लशिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह एक नियमित रखरखाव प्रक्रिया

होती है, जिसमें जलाशयों की सफाई की जाती है ताकि पानी की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। इस फ्लशिंग प्रक्रिया के चलते हिंदू राव रिजर्वॉयर से पानी पाने वाले इलाकों में दो दिनों तक सप्लाई प्रभावित रहेगी।

इसके अलावा, पश्चिमी दिल्ली में 900 मिमी व्यास की नई पानी की पाइपलाइन को छह अलग-अलग स्थानों पर इंटरकनेक्ट किया जा रहा है, जिससे वहां भी जल आपूर्ति रोकी जा रही है। नई 900 मिमी डायामीटर की ख्याला मेन पाइपलाइन को इन 6 जगहों पर जोड़ा जा रहा है। जिसमें पंजाबी बाग क्लब, पंजाबी बाग रिजर्वॉयर, राम देव मार्ग, ख्याला इढर और नजफगढ़ नाले के दोनों ओर जोड़ा जा रहा है। इसी तकनीकी काम की वजह से कई कॉलोनियों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी।

इन इलाकों में रहेगी पानी की किल्लत

नारायणा कमांड एरिया, इंदरपुरी, तोड़ापुर गांव, नारायणा गांव, नारायणा विहार, कृषि कुंज, मानसरोवर गार्डन, राजौरी गार्डन और आसपास, राजौरी गार्डन

इंदौर : पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा समेत तीन की मौत, बायपास पर कार-ट्रक का एक्सीडेंट

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार अलसुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। तेजाजी नगर बायपास पर रालामंडल के समीप एक तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई।

इस हादसे में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री एवं वर्तमान में राजपुर विधायक बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है।

अलसुबह हुआ हादसा, कार के उड़े परखच्चे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा तड़के उस वक्त हुआ जब कार तेजाजी नगर बायपास से गुजर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को बाहर निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

हादसे में प्रेरणा बच्चन, मन संधू और प्रखर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार घायल युवती की हालत नाजुक बनी हुई है।

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

हादसे की सूचना मिलते ही तेजाजी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और संभवतः लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।

'सीएए आंदोलन से दिल्ली दंगों से पहले अलग हो चुका था', शरजील इमाम का अदालत में दावा

(जीएनएस)।

स्टूडेंट एक्टिविस्ट और 2020 दिल्ली दंगे के आरोपों में जेल में बंद शरजील इमाम ने अदालत में बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा से काफी पहले नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ चल रहे आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था।

इमाम ने कहा कि उनके कुछ सह-आरोपियों ने ही उनसे आंदोलन से दूर रहने को कहा था, क्योंकि उनके भाषणों से आंदोलन को "सांप्रदायिक रंग" मिलने की आशंका जताई जा रही थी। यह बयान इस मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब शरजील इमाम ने खुद को अन्य सह-आरोपियों से स्पष्ट रूप से अलग करने

की कोशिश की है।

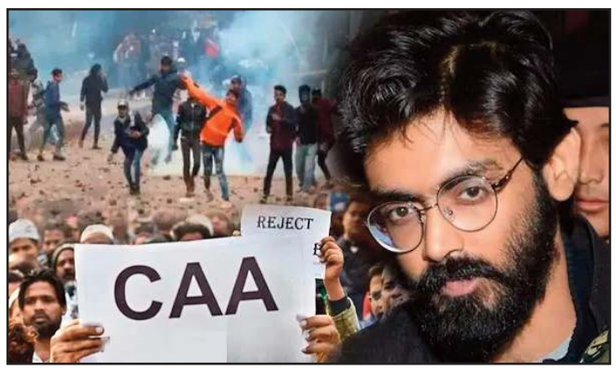

अदालत में क्या बोले शरजील इमाम के वकील?

कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजाज के समक्ष पेश होते हुए शरजील इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के ही रिकॉर्ड से यह साफ होता है कि इमाम को आंदोलन के बीच में ही किनारे कर दिया गया था और फरवरी 2020 के दंगों से जुड़ी किसी भी कथित साजिश में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

मुस्तफा ने अदालत में कहा,अन्य आरोपियों को लगने लगा था कि आंदोलन सांप्रदायिक दिशा में जा रहा है और चूंकि शरजील इमाम एक जाना-पहचाना चेहरा थे, इसलिए उन पर इसका आरोप आएगा। इसी वजह से उन्होंने 2 जनवरी 2020 तक आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। उस समय तक कहीं भी हिंसा नहीं हुई थी।"

दिसंबर 2019 तक सीमित भूमिका

'पहले गोली मारेंगे, बाद में बात करेंगे', डेनमार्क ने ट्रंप को सिखाई तमीज, दिया तगड़ा डोज

(जीएनएस)।

डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को कथित तौर पर एक बेहद सख्त निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करता है, तो डेनिश सैनिकों को "पहले गोली चलाने और बाद में सवाल पूछने" की अनुमति होगी। यह निर्देश ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की धमकी दे रहे हैं।

ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है

ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन यह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। अमेरिका की ओर से बार-बार दिए जा रहे बयानों के कारण डेनमार्क में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने पुराने लेकिन अब भी लागू नियमों की पुष्टि की है।

डेनिश अखबार 'बर्लिंग्सके' का बड़ा खुलासा

स्थानीय अखबार 'बर्लिंग्सके' से

बातचीत में डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ग्रीनलैंड में तैनात सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगर वहां किसी भी विदेशी ताकत द्वारा हमला किया जाता है, तो सैनिकों को किसी वरिष्ठ अधिकारी या सरकार के आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत कार्रवाई करने की अनुमति होगी।

1952 के शीत युद्ध काल के नियम का हवाला

यह आदेश कोई नया नियम नहीं है। यह 1952 के शीत युद्ध (उङ्म'ी हं१) के दौर में बनाए गए एक नियम का हिस्सा है। इस नियम के तहत सैनिकों को किसी भी विदेशी आक्रमण की स्थिति में "तुरंत मोर्चा संभालने" और जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

आदेश आए या न आए, कार्रवाई जरूरी

एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के अनुसार, इस नियम में साफ लिखा है कि सैनिकों को "आदेशों का इंतजार किए बिना या मांगे बिना" कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही उनके कमांडर को यह जानकारी न हो कि युद्ध की औपचारिक घोषणा हुई है या नहीं।

1940 के नाजी हमले से जुड़ी है इस नियम की जड़

इस नियम की जड़ें 1940 में हुए नाजी जर्मनी के हमले से जुड़ी हैं। उस समय जर्मन सेना ने कोपेनहेगन समेत डेनमार्क के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। डेनिश सेना उस हमले का प्रभावी तरीके से मुकाबला नहीं कर पाई थी।

उसी हार से जन्मा "पहले गोली" वाला सिद्धांत

1940 की उस हार के बाद डेनमार्क ने महसूस किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए। इसी सोच से "पहले गोली चलाने" का नियम बनाया गया, ताकि सैनिक किसी भी हमलावर के सामने हिचकिचाएं नहीं। यह आदेश तब से आज तक लागू है।

डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं?

अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं? हाल के वर्षों में ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है।

थलपति विजय की 'जन नायकन' पर मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CBFC को दिया ऐसा आदेश

(जीएनएस)।

तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की बहुचर्चित फिल्म 'जन नायकन' को लेकर चल रहा सर्टिफिकेशन विवाद अब आखिरकार खत्म हो गया है। फिल्म की रिलीज को लेकर बीते दिनों काफी हंगामा देखने को मिला था लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद मेकर्स और फैंस दोनों को बड़ी राहत मिली है।

मद्रास हाई कोर्ट ने CBFC को दिया ऐसा आदेश

कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को निर्देश दिया है कि फिल्म को व/अ सर्टिफिकेट जारी किया जाए जिससे इसकी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है।

खंल्ल ठंटॅल्ल 9 जनवरी 2026 की रिलीज क्यों टली थी?

-दरअसल थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को पहले 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। इसी दिन प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' भी रिलीज हो रही थी।

-हालांकि आखिरी समय पर उइत्रळ से सर्टिफिकेट न मिलने के कारण थलपति विजय की फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन करना पड़ा था जिससे फैंस में नाराजगी देखने को मिली थी।

हाई कोर्ट ने उइत्रळ के फैसले को बताया गलत

-मामला जब मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने उइत्रळ की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने साफ कहा कि उइत्रळ चेयरपर्सन के पास फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजने का अधिकार नहीं था।

-इसके साथ ही कोर्ट ने गत 6 जनवरी 2026 को जारी किए गए उइत्रळ के लेटर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड को तुरंत व/अ सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद फिल्म की रिलीज को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी मिल गई है।

अब कौन देख सकता है 'जन नायकन'?

व/अ सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों के लिए नियम भी साफ हो गए हैं। अब इस फिल्म को सभी उम्र के दर्शक देख सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चे केवल पैरेंट्स या गार्जियन के साथ थिएटर में एंट्री ले सकते हैं। वहीं 12 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों के लिए कोई रोक नहीं होगी।

27 कट लगाने के बाद भी अटका था मामला

-जानकारी के अनुसार 'जन नायकन' को 18 दिसंबर 2025 को CBFC के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था। उस वक्त बोर्ड की ओर से फिल्म में 27 कट लगाने के निर्देश दिए गए थे।

वेनेजुएला मुद्दे पर ट्रंप को झटका,अमेरिकी सीनेट ने सैन्य कार्रवाई के अधिकार पर लगाई लगाम

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला के मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने एक अहम प्रस्ताव पारित करते हुए कांग्रेस की मंजूरी के बिना वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने से राष्ट्रपति को रोकने के पक्ष में वोट किया है।

यह प्रस्ताव 52-47 मतों से पास हुआ, जिसमें ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के पांच सीनेटरों ने भी उनके खिलाफ मतदान कर दिया। इससे न केवल ट्रंप की विदेश नीति पर सवाल उठे हैं, बल्कि उनकी पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति भी खुलकर सामने आ गई है।

क्या है पूरा मामला?

सीनेट में लाया गया यह प्रस्ताव वेनेजुएला में संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने के उद्देश्य से पेश किया गया था। प्रस्ताव के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका किसी भी देश के खिलाफ युद्ध या सैन्य अभियान कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना नहीं चला सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में आगे कोई सैन्य कदम उठाना चाहता है, तो उसे पहले अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी होगी।

यह फैसला राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति के सैन्य कार्रवाई कितनी दूर तक कर सकता है।

ट्रंप की पार्टी में भी फूट

इस वोटिंग की सबसे अहम बात यह रही कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पांच सीनेटरों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। जिससे वोटिंग में ट्रंप के पक्ष में 47 वोट और उनके खिलाफ 52 वोट पड़े। इससे यह साफ हो गया है कि वेनेजुएला नीति को लेकर खुद रिपब्लिकन खेमे में भी असहमति है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति और सैन्य हस्तक्षेप के तरीकों को लेकर बढ़ती बेचैनी का संकेत है।

अभी कानून बनना बाकी

हालांकि, यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है। अमेरिकी व्यवस्था के अनुसार, इसे संसद के दूसरे सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पारित होना जरूरी है। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा। ट्रंप के पास इसे वीटो करने का अधिकार भी है, लेकिन सीनेट में हुई यह वोटिंग उनके लिए राजनीतिक रूप से मुश्किलें जरूर बढ़ा सकती है।

वोटिंग का क्या होगा असर?

राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, इस फैसले के कई असर हो सकते हैं-

राष्ट्रपति ट्रंप पर घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ेगा।

अमेरिकी सेना बिना संसद की मंजूरी के किसी भी कार्रवाई से पहले ज्यादा सतर्क रहेगी।

रूस और चीन को यह संदेश जाएगा कि अमेरिका की सत्ता व्यवस्था के भीतर मतभेद हैं।

ग्रीनलैंड जैसे मामलों पर यूरोप को कुछ राहत महसूस हो सकती है।

भारत जैसे देशों के "स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी" सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिल सकती है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी सख्ती जारी

सीनेट के इस फैसले के बावजूद अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अपनी सख्ती कम नहीं की है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भी अमेरिकी सेना कैरिबियन क्षेत्र में तैनात है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ड्रग तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल जहाजों और नावों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला की ओर जा रहे एक रूसी तेल टैंकर को भी जब्त किया था, जिससे रूस और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है।

ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम नेता और मादुरो की पूर्व सहयोगी डेल्सी रोड्रिगेज को भी कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर उन्होंने अमेरिका की शर्तें नहीं मानीं, तो उन्हें मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कोलंबिया और ग्रीनलैंड के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है।

ट्रंप प्रशासन का साफ कहना है कि अमेरिका लंबे समय तक वेनेजुएला की सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहता है और वहां के विशाल तेल उद्योग को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहता है। हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस रणनीति में अमेरिकी सेना की भूमिका क्या होगी और भविष्य में इसे किस तरह लागू किया जाएगा। अमेरिकी सीनेट का यह फैसला ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

क्या है DIRBS तकनीक? जिसने एक झटके में 10 करोड़ मोबाइल फोन्स को बना दिया डब्बा

(जीएनएस)।

पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी (PTA) ने वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि देश में सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन के चलते लगभग 10 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई का मुख्य निशाना नकली, क्लोन किए गए और चोरी के फोन रहे हैं।

इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं का डेटा सुरक्षित हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के घरेलू मोबाइल निर्माण उद्योग को भी जबरदस्त संजीवनी मिली है। भारत जैसे बड़े मोबाइल बाजार के लिए यह एक उदाहरण है कि कैसे तकनीक के जरिए सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को सुधारा जा सकता है।

नकली और क्लोन डिवाइस पर कड़ा प्रहार

PTA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक किए गए कुल 10 करोड़ हैंडसेट्स में से लगभग 7.2 करोड़ फोन नकली या डुप्लीकेट पाए गए। इसके अलावा, 2.7 करोड़ ऐसे फोन थे जिनके क्टएक नंबरों के साथ छेड़छाड़ या क्लोनिंग की गई थी। इस बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई ने उन अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ दिया है जो सस्ते और असुरक्षित डिवाइस बेचकर ग्राहकों की गोपनीयता और सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। यह कदम डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए अनिवार्य था।

DIRBS: सुरक्षा और नेटवर्क का तालमेल

DIRBS एक अत्याधुनिक प्रणाली है जिसे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट रेगुलेशन के तहत लागू किया गया है। यह सिस्टम हर मोबाइल के रजिस्ट्रेशन को उसके नेटवर्क ऑथराइजेशन से जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग या अनधिकृत तरीके से लाए गए फोन अब काम नहीं कर पाएंगे। केवल वही डिवाइस सक्रिय हो सकेंगे जो नियमों के अनुरूप हैं। इस पारदर्शिता ने अवैध तस्करी पर लगाम लगाई है और मोबाइल मार्केट को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया है।

स्थानीय निर्माण में ऐतिहासिक उछाल

सख्त नियमों का सबसे सकारात्मक असर पाकिस्तान के घरेलू उद्योग पर दिखा है। साल 2025 तक पाकिस्तान में उपयोग होने वाले 95% डिवाइस स्थानीय स्तर पर ही निर्मित हो रहे हैं, जिनमें 68% स्मार्टफोन्स शामिल हैं। सैमसंग, शाओमी और वीवो जैसी 36 प्रमुख कंपनियों ने वहां अपनी यूनिट्स स्थापित की हैं। जब नकली और स्मगल किए गए विदेशी फोन ब्लॉक हुए, तो बाजार में मांग बढ़ी, जिससे स्थानीय उत्पादन और रोजगार के नए अवसरों को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है।

भारत के लिए सबक

भारत में भी नकली और क्लोन स्मार्टफोन्स का बाजार एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भी ऊक्रफइर जैसा सख्त सिस्टम अपनाना चाहिए। इससे न केवल कर चोरी रुकेगी और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि उन करोड़ों ग्राहकों की प्राइवेसी भी सुरक्षित रहेगी जो अनजाने में असुरक्षित और नकली प्रीमियम डिवाइस खरीद लेते हैं।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-2026: सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और पोरबंदर का गौरवशाली योगदान

गांधीनगर, 09 जनवरी : भारतीय संस्कृति के राष्ट्रीय स्वाभिमान और अजेय आस्था के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के सान्निध्य में 8 से 11 जनवरी तक 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए सोमनाथ की धरा पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में, पोरबंदर के जाने-माने इतिहासकार श्री नरोतमभाई पलाण ने इस गौरवशाली इतिहास के पन्नों को खोलकर पोरबंदर के अप्रतिम योगदान के संस्मरणों को याद किया है।

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री नरोतमभाई पलाण ने कहा कि जनवरी, 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस घटना को जनवरी, 2026 में ठीक 1000 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह तारीख 6 जनवरी है।

उन्होंने कहा कि सोमनाथ का प्रथम मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है। शुरूआत के 1000 सालों तक यह मंदिर अत्यंत समृद्ध और अटूट रहा, जिसकी ख्याति सुनकर गजनवी ने उस पर आक्रमण किया था। हालांकि, सोमनाथ प्रजा के स्वाभिमान का प्रतीक है। जब-जब इस मंदिर को तोड़ा गया, तब-तब प्रजा और राजाओं ने मिलकर उसे फिर से खड़ा किया। मंदिर का मौजूदा स्वरूप आठवीं बार का पुनर्निर्माण है।

सौराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उछरंगराय ढेबर ने दान एकत्र करने की अपील की थी। श्री नरोतमभाई पलाण ने गर्व से कहा कि सोमनाथ मंदिर के नवनिर्माण के लिए पहला योगदान पोरबंदर ने दिया था।

पोरबंदर के विख्यात शेठ नानजी कालिदास मेहता ने उस जमाने में मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का पहला दान दिया था। साथ ही, उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि आवश्यकता पड़ने पर वे और भी दान देने को तैयार हैं।

उन्होंने अंत में कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सनातन धर्म की दृढ़ता और विजय का जयघोष है। पोरबंदर सदैव इस पवित्र कार्य में आगे रहा है, जो हरेक पोरबंदरवासी के लिए गौरव की बात है।

सीएम योगी ने यूपी दिवस 2026 की तैयारियों की प्रगति को लेकर उच्चाधिकारियों संग समीक्षा बैठक

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवसझ्र2026 की तैयारियों की प्रगति को लेकर उच्चाधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम बने। आगामी 24 से 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी जनपदों, देश के सभी राजभवनों एवं विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में यूपी दिवस का भव्य आयोजन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर यूपी दिवसझ्र2026 का मुख्य समारोह आयोजित होगा। प्रदेश की ऐतिहासिक और वैचारिक विरासत को

जनमानस से जोड़ने के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, 'भारत रत्न' सरदार वल्लभभाई पटेल, वंदे मातरम्-आनंद मठ और पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होल्कर से जुड़े नाट्य मंचनों का आयोजन किया जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा वंदे मातरम् रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आनंद मठ आधारित विशेष प्रस्तुतियां प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त रूप देंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यूपी दिवसझ्र2026 के अवसर पर देश-विदेश में बसे प्रवासी उत्तर प्रदेशवासियों से संवाद स्थापित किया जाए। इसके साथ ही राजभवनों व दूतावासों में मंत्रीगण की उपस्थिति में आयोजन किया जाए, वहीं जनपद स्तर पर उद्यमी, किसान, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, महिलाएं एवं उत्कृष्ट नागरिक 'यूपी गौरव' सहित विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किए जाएं। यूपी दिवसझ्र2026 को जन उत्सव का स्वरूप देते हुए सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, नाट्य मंचन, लोक-संगीत, ओडीओपी, ओपन माइक, नुक्कड़ नाटक और आधुनिक तकनीक आधारित 3-डी, वीआर, 360ट टूर व लघु फिल्में, क्विज प्रतियोगिताएं और छायाचित्र प्रदर्शनी आयोजित होंगी।

मिशन शक्ति 5 के तहत पीलीभीत महिला थाना पुलिस ने महिलाओं-बालिकाओं को अपराधों से बचाव के लिए किया जागरूक

(जीएनएस)।

पीलीभीत। DIG/SP पीलीभीत के निर्देशन में मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत महिला थाना पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें संभावित खतरों से अवगत कराना है, ताकि वे स्वयं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

महिला थाना प्रभारी ने बताया कि टीम ने गांवों, मोहल्लों और बाजार क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं व बालिकाओं के बीच जागरूकता सत्र आयोजित किए। इन सत्रों में पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090, 181 और 112 की जानकारी दी गई। साथ ही, साइबर अपराधों जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल्स, सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ और नकली ऐप्स से बचाव के टिप्स साझा किए गए। महिलाओं को सलाह दी गई कि वे संदिग्ध मैसेज या कॉल्स पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें।

अभियान के दौरान टीम ने 200 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद किया। कई महिलाओं ने अपनी समस्याएं साझा कीं, जिनमें घरेलू हिंसा, स्टॅल्ल और ऑनलाइन धमकियां शामिल थीं। पुलिस ने इन शिकायतों का तुरंत संज्ञान लिया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक बालिका ने बताया कि उसे सोशल मीडिया पर अजनबी से अनुचित मैसेज मिले थे, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई और तत्काल ब्लॉक करने की सलाह दी गई।

मिशन शक्ति 5 उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान पर केंद्रित है। पीलीभीत जिले में यह अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस, प्रशासन और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। उक्क्ररढ ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाए जाएं, ताकि कोई भी महिला या बालिका असुरक्षित महसूस न करे। आने वाले दिनों में स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

इस पहल से क्षेत्र की महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अब खुलकर अपनी बात रख रही हैं। जागरूकता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है, यही संदेश अभियान के माध्यम से दिया जा रहा है।

पीलीभीत में धारा 163 लागू: त्योहारों व परीक्षाओं के लिए सख्ती, लाउडस्पीकर बिना अनुमति बंद,अराजक तत्वों पर नजर

(जीएनएस)।

पीलीभीत।आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह ने पूरे जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और मार्च के प्रथम सप्ताह तक प्रभावी रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि कुछ संगठन या असामाजिक तत्व निजी स्वार्थों के लिए समाज में वैमनस्य व द्वेष फैला सकते हैं। ऐसे अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

प्रमुख प्रतिबंध:

- सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडा, बंदूक, पिस्टल, तलवार या धारदार चाकू जैसे हथियार ले जाना प्रतिबंधित।
- पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना वर्जित; सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जुलूस या जनसभा नहीं।
- छतों या घरों के सामने ईंट, पत्थर, तेजाब या विस्फोटक सामग्री का संग्रह निषिद्ध।
- लाउडस्पीकर बिना अनुमति के नहीं बज सकेंगे; रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध।
- अस्पताल व शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे को 'साइलेंस जोन' घोषित।
- सोशल मीडिया या सार्वजनिक रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर,लेख या भाषण प्रतिबंधित।
- बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना वर्जित।

छूट: ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, सिख समुदाय को कृपाण व वृद्धों को सहारे की लाठी पर छूट।

जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि शांति बनाए रखने में सहयोग करें। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

कनपरी गांव में तालाब पर दबंगों का अवैध मकान निर्माण, लेखपाल पर लापरवाही रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का आरोप

(जीएनएस)।

पीलीभीत,9 जनवरी। बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव कनपरी में दबंगों द्वारा तालाब में मकान निर्माण का मामला सामने आया है, जिसमें तहसील प्रशासन की मिलीभगत साफ झलक रही है। पीड़ित की बार-बार शिकायतों को अनदेखा कर लेखपाल ने भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास किया।

प्रशासन की उदासीनता

तहसील प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को रोकने के बजाय चुप्पी साध रखी है, जिससे ग्रामीणों में भारी

आक्रोश व्याप्त है। दबंगों को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं, जबकि जल स्रोतों की रक्षा का दायित्व प्रशासन का है। पीड़ित का कहना है कि शिकायतें दर्ज करने पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

लेखपाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम

लेखपाल ने न केवल शिकायत का ठीक से संज्ञान लिया, बल्कि मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की। ग्रामीणों का आरोप है कि रिश्वतखोरी से प्रेरित होकर राजस्व कर्मी दोषियों को बचाने में जुटे हैं। इस लापरवाही से तालाब का जल स्तर घट रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।

ग्रामीणों की मांग

जिला प्रशासन से तत्काल जांच, अवैध निर्माण ध्वस्त करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में हैं। प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी वरना आंदोलन और उग्र हो सकता है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली रेडक्रॉस पूरी ठंड सोई रही,अब राहत भी 'चुपचाप' हरदोई में रेडक्रॉस की कार्यशैली एवं निष्क्रियता पर उठे सवाल

वितरण सामग्री लाभार्थियों को गिनी चुनी बांट कर नजदीकियों व नौकर चाकरों को बाँट कर किया जाता है बंदर बाँट

(जीएनएस)।

लखनऊ। हरदोई जिले में इस वर्ष भीषण ठंड ने गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रेडक्रॉस सोसायटी हरदोई की भूमिका पूरे शीतकाल में लगभग नदारद रही। दिसंबरझ्रजनवरी के दौरान जब तापमान लगातार गिरता रहा, तब जिले की अनेक सामाजिक, धार्मिक व स्वयंसेवी संस्थाओं ने कंबल वितरण, अलाव और राहत सामग्री बांटकर मानवीय जिम्मेदारी निभाई, वहीं रेडक्रॉस सोसायटी की चुप्पी अब भी सवालों के घेरे में है। पूरे जाड़े के मौसम में रेडक्रॉस द्वारा किसी भी बड़े या संगठित राहत कार्यक्रम की जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। न गरीबों के लिए कंबल वितरण हुआ, न बेसहारा लोगों के लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया। सामाजिक कार्यकताओं का कहना है कि जिस संस्था का उद्देश्य ही आपदा और संकट के समय मानव सेवा करना है उसकी यह निष्क्रियता बेहद चिंताजनक है। खासकर तब, जब रेडक्रॉस को संसाधनों और प्रशासनिक संरक्षण की कोई कमी नहीं मानी जाती है। अब ठंड लगभग समाप्त होने के बाद 8 जनवरी को लोनार थाना क्षेत्र अंतर्गत आग लगने की एक घटना में रेडक्रॉस द्वारा कुछ राहत सामग्री बांटे जाने की बात सामने आई है लेकिन यह राहत कार्य भी विवादों में घिर गया है। बताया जा रहा है कि यह वितरण बेहद चुपचाप किया गया, न तो इसकी कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही सोसायटी की प्रबंध कमेटी को विधिवत अवगत कराया गया। केवल सभापति एवं एक दो सदस्यों द्वारा अपनी व्यक्तिगत वाहवाही के लिए ये वितरण किया गया। सूत्रों द्वारा ये भी खबर है कि वितरण के लिए ले जाई गई सामग्री लाभार्थियों को गिनी चुनी बांटी जाती है बल्कि पदाधिकारियों द्वारा राहत सामग्री का अपने नजदीकियों और नौकर चाकरों को बाँट कर बंदरबाँट कर लिया जाता है। अब यहां सवाल उठता है? राहत सामग्री का वितरण गुपचुप क्यों? रेडक्रॉस सोसायटी के ही कई पदाधिकारियों और सदस्यों ने इस राहत वितरण के तरीके पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि बिना कमेटी को जानकारी दिए, बिना किसी ठोस निर्णय या प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के राहत सामग्री बांटना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि संस्था के नियमों के भी खिलाफ है। आरोप है कि यह पहली बार नहीं हुआ है, पूर्व में भी जब कभी राहत सामग्री बांटी गई, तब उसकी जानकारी प्रबंध कमेटी के अधिकांश सदस्यों को नहीं दी गई। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब संस्था के अध्यक्ष जिलाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष स्वयं राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर आसीन हैं, तब भी रेडक्रॉस की कार्यप्रणाली इतनी अपारदर्शी क्यों है? क्या पूरी प्रबंध कमेटी के होते हुए भी निर्णय केवल संस्था के सभापति स्तर पर ही लिए जाते हैं और बाकी सदस्य मूक दर्शक बने रहते हैं? क्या चुपचाप सामग्री का बंदरबाँट करने के लिए ही प्रबंध कमेटी एवं अन्य सदस्यों को सूचना नहीं दी जाती है? अब जिले में यह मांग तेज हो रही है कि रेडक्रॉस

पीलीभीत में विकास प्राधिकरणों की अनियमितताओं पर समीक्षा बैठक

(जीएनएस)।

पीलीभीत, 9 जनवरी 2026: गांधी सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों तथा नगर निगमों में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने एवं जांच संबंधी समिति द्वारा आहूत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की।

इस बैठक का उद्देश्य विकास कार्यों में हो रही अनियमितताओं की गहन जांच करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। समिति के सदस्यों ने विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी तथा अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पीलीभीत जिले के विकास प्राधिकरण, आवास विकास, जिला पंचायत राज तथा नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निर्माण कार्यों, बजट उपयोग तथा शिकायत निस्तारण पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अनियमितताओं की शिकायतों पर तत्काल जांच समितियां गठित की जाएंगी तथा दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लेते हुए जनहित के मुद्दों को उठाया तथा पारदर्शी विकास की मांग की। जिला मजिस्ट्रेट ने समिति को आश्वासन दिया कि सभी सुझावों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

यह बैठक पीलीभीत जिले में शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं जवाबदेही बढ़ेगी।

करछना तहसील में सीज जमीन पर खुलेआम खेती, आईजीआरएस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई शून्य।

(जीएनएस)।

लखनऊ/प्रयागराज

करछना तहसील क्षेत्र में प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। तहसील प्रशासन द्वारा सीज की गई भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही है, जबकि इस संबंध में IGRS पोर्टल पर शिकायत 40017520081777 भी दर्ज कराई जा चुकी है, इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

जानकारी के अनुसार, संबंधित भूमि को प्रशासन द्वारा पूर्व में सीज किया गया था, लेकिन स्थानीय दबंगों द्वारा फसल बोकर खेती की जा रही है। इससे न केवल प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना हो रही है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ता महेश सिंह पुत्र राजबहादुर ग्राम बबुरा परगना अरेल करछना प्रयागराज का आरोप है कि क्क्रक्र पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर निरीक्षण तक नहीं कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि या तो शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, या फिर मिलीभगत के चलते कार्रवाई टाली जा रही है।

स्थानीय लोगों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि यदि सीज जमीन पर खुलेआम खेती होती रही और प्रशासन मौन रहा, तो आम जनता का कानून से भरोसा उठ जाएगा।

राजूपुर कुंडरी की गौशाला में प्रधान पति की दबंगई!भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप, अधिकारी बने मौन दर्शक

(जीएनएस)।

पीलीभीत/बीसलपुर ग्राम राजुपुर कुंडरी की गौशाला को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार गौवंश संरक्षण और गौशालाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और दबंगई की तस्वीरें इन योजनाओं की साख पर सवाल खड़े कर रही हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के पति ने गौशाला पर पूरी तरह कब्जा जमा रखा है। गौशाला के अंदर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही। जब कुछ ग्रामीण और स्थानीय पत्रकार स्थिति देखने पहुंचे, तो प्रधान पति ने उन्हें जबरन रोक दिया। उन्होंने दावा किया कि ह्लअंदर जाने पर अधिकारियों ने रोक लगा रखी हैह्व, लेकिन जब यह बात क्षेत्रीय बीडीओ से पूछी गई तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है।जांच में यह भी सामने आया कि गौशाला की देखरेख में लगे कर्मचारी प्रधान पति के इशारे पर मनमानी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला में रखी चारे और मवेशियों की स्थिति दयनीय है, जबकि रिकॉर्ड में सब कुछ ह्लसहीह्व दिखाया जा रहा है।गांव के कुछ लोगों ने यह भी बताया कि इसी प्रधान पति पर पहले ह्लमगरमच्छ मारने के मामले के दौरान चर्चा में रह चुके हैं लोगों का कहना है क्या पता हिंदुओं की गौ माता से ले रहे हैं यह बदला लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस

कार्रवाई नहीं की गई। इसका नतीजा यह है कि अब वही व्यक्ति खुलेआम सरकारी व्यवस्था को चुनौती देता नजर आ रहा है।जब पत्रकारों ने शासन-प्रशासन से जवाब मांगा तो अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे। और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नूरुददीन से बात की गई तो उन्होंने कहा मामला यहीं पर खत्म कर दो पहले भी चर्चा में रह चुका है मामला। बीडीओ से लेकर पशु अधिकारी तक किसी ने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इससे सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई गौशाला के भीतर छिपाई जा रही है, जिससे जनता को दूर रखा जा रहा है?स्थानीय नागरिकों की मांग है कि शासन इस पूरे मामले में स्वतंत्र जांच कराए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जनता का भरोसा सरकारी योजनाओं से उठ न जाए।संपादकीय टिप्पणी:

राजुपुर कुदरी का यह मामला केवल एक गांव या एक गौशाला तक सीमित नहीं है। यह उस भ्रष्ट तंत्र का प्रतीक है, जहां कुछ प्रभावशाली लोग सरकारी योजनाओं को अपने निजी हितों का साधन बना लेते हैं। अगर प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो ऐसी घटनाएं जनविश्वास को गहरा धक्का पहुंचाएंगी।स्थानीय सूत्रों के अनुसार, गौशाला में रखी गई कई गायें रोजाना दम तोड़ रही हैं और मृत पशुओं को खुले में फेंक दिया जाता है। कुत्तों और कौवों द्वारा मृत गायों को नोचने के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है।गौरतलब है कि संबंधित प्रधान पति पर इससे पहले भी वन विभाग की कार्रवाई के दौरान विवादित मामले दर्ज हो चुके हैं।

25 वर्षीय युवती की टृक की चपेट मे आने से दर्दनाक मौत

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी । भाई के साथ दवा लेकर बाईक से लौट रही एक 25 वर्षीय युवती की टृक की चपेट मे आने से दर्दनाक मौत हो गयी पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे थाना मसौली क्षेत्र के ब्लाक कालोनी के निकट रहने वाली 25 वर्षीय युवती सफीना पुत्री जलील

अपने भाई मो0 आरिफ के साथ जैदपुर दवा लेकर बाईक नम्बर यूपी 41 बी डी 9695 से घर वापस लौट रहे थे कि सफदरगंज थाना क्षेत्र के बदोसराय सफदरगंज पर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सामने स्थित झंझरिया पुल के निकट बाईक अनियंत्रित होकर पलट गयी इसी दौरान आ रहा टृक नम्बर यूपी 67 ए टी 2794 के पहिये के नीचे आने से युवती की दर्दनाक मौत हो गयी। सफदरगंज पुलिस ने एम्बूलैंस से सीएचसी बड़ागांव लेकर गये जहा चिकित्स्को ने मृत घोषित कर दिया मसौली पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बीसलपुर तहसील प्रशासन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप,

लेखपाल की भूमिका संदिग्ध

(जीएनएस)। पीलीभीत/बीसलपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम कनपरी से सामने आया यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस तरह सरकारी तंत्र दबंगों के आगे नतमस्तक होता जा रहा है।

आरोप है कि लेखपाल ने मोटी रिश्वत लेकर पारम्परिक तालाब और चकरोड की सरकारी भूमि दबंगों के हवाले कर दी, जिस पर अब खुलेआम अवैध निर्माण कराया जा रहा है।अभिलेखों के अनुसार दबंगों के नाम लगभग 12 बीघा भूमि दर्ज है, लेकिन जब तहसील प्रशासन द्वारा पैमाइश कराई गई तो कब्जा 14 बीघा निकला।नियमों के तहत जहाँ 2 बीघा अतिरिक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाना चाहिए था, वहीं लेखपाल ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय उसी अवैध भूमि पर आवास निर्माण की अनुमति दे दी।

भाकियू किसान नेता पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा में फंसाने की कोशिश करते ग्राम प्रधान

(जीएनएस)।

हरदोई/शाहाबाद थाने के ग्राम पंचायत आगापुर के प्रधान अखिलेश कुमार झूठे आरोप लगाकर हरीजन एक्ट मारपीट करने जैसे मुकदमे में फंसाने के लिए अपने करीबी अनिल कुमार पुत्र श्रीकृष्ण निवासी आगापुर को लेकर आज कई महीनों से प्रर्थना पत्र देकर गलत आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं किसान नेता सत्यवीर सिंह ने न्याय की गुहार क्षेत्राधिकारी आलोक राज नारायण से लगाई और बताया कि हम जिस समय की घटना बताई जा रही है उस समय रिफाकत ब्रिक फिल्ड भट्टा पर ईंट लेने गए थे और मुनीम से बात कराने का ऑडियो भी है और कई लोग किसान नेता के साथ थे किसान नेता के दिए हुए प्रर्थना पत्र पर पुलिस जांच कर रही है।